

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1784 का उत्तर

उत्तर प्रदेश में रेलवे परियोजनाएँ

1784. श्री आर. के. चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 16 नई लाइन परियोजनाओं और 3 आमामान परिवर्तन परियोजनाओं (कुल मिलाकर क्रमशः लगभग 1,740 किमी और 261 किमी) में से लागत की दृष्टि से तीन सबसे बड़ी परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार विशिष्ट पूर्णता प्रतिशत और आरंभ करने की संशोधित लक्ष्य तिथि क्या है;
- (ख) भारतीय रेलवे में स्वीकृत रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) की अधिक संख्या को देखते हुए, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नए आरओबी/आरयूबी आरंभ किए गए हैं;
- (ग) मोहनलालगंज क्रॉसिंग (लखनऊ-रायबरेली खंड) पर ओवरब्रिज परियोजना को पूरा करने की विशिष्ट समय-सीमा क्या है;
- (घ) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में चिन्हित 157 स्टेशनों के पुनर्विकास की स्टेशन-वार अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना के तहत पूर्ण रूप से क्रियान्वित रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/जिला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक

आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

उत्तर प्रदेश

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रुपए (लगभग 18 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 किलोमीटर	199 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-25	5,272 किलोमीटर	479 किलोमीटर प्रतिवर्ष (2 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 62,360 करोड़ रुपए लागत पर 3,807 किलोमीटर कुल लंबाई की 49 परियोजनाएं (10 नई लाइन, 02 आमामान परिवर्तन और 37 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	10	1227	340	10517
आमामान परिवर्तन	02	67	0	281

दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	37	2513	983	19813
कुल	49	3807	1323	30611

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	डोमिनगढ़-गोरखपुर-कुसुम्ही - तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण (21 किलोमीटर)	508
2	बहराइच-नानपारा-नेपाल गंज आमान परिवर्तन (56 किलोमीटर)	342
3	बलिया-गाजीपुर सिटी दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	650
4	गाजीपुर सिटी-तारीघाट नई लाइन (17 किलोमीटर)	1766
5	गोंडा-गोरखपुर लूप आमान परिवर्तन (260 किलोमीटर)	863
6	गोंडा-बहराइच आमान परिवर्तन (60 किलोमीटर)	318
7	बाराबंकी-अकबरपुर दोहरीकरण (161 किलोमीटर)	1700
8	कप्तानगंज-थावे-छपरा आमान परिवर्तन (234 किलोमीटर)	819
9	पीलीभीत-शाहजहांपुर आमान परिवर्तन (83 किलोमीटर)	589
10	इंदारा-दोहरीघाट आमान परिवर्तन (34 किलोमीटर)	213
11	लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन (263 किलोमीटर)	1634
12	भदोही-जंघई दोहरीकरण (31 किलोमीटर)	168
13	लहोटा-भदोही दोहरीकरण (39 किलोमीटर)	184
14	मेरठ-मुजफ्फरनगर दोहरीकरण (55 किलोमीटर)	430
15	फाफामऊ-प्रयागराज दोहरीकरण (14 किलोमीटर)	212
16	मुजफ्फरनगर-टपरी दोहरीकरण (52 किलोमीटर)	525
17	उतरेटिया-रायबरेली दोहरीकरण (66 किलोमीटर)	662

18	रायबरेली-अमेठी दोहरीकरण (60 किलोमीटर)	668
19	आलमनगर-उतरेटिया दोहरीकरण (20 किलोमीटर)	358
20	भीमसेन-झांसी दोहरीकरण (206 किलोमीटर)	2620
21	इटावा-मैनपुरी नई लाइन (58 किलोमीटर)	313
22	मल्हौर-डालीगंज दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	183
23	रूमा चकेरी- चंदारी तीसरी लाइन (13 किलोमीटर)	177
24	बरेली-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन (102 किलोमीटर)	313
25	रोसा-सीतापुर कैंट-बुढ़वल दोहरीकरण (181 किलोमीटर)	2094
26	जौनपुर-अकबरपुर (टांडा) दोहरीकरण (77 किलोमीटर)	676
27	रमना-रेणुकूट-सिंगरौली दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	2436
28	जंघई-फाफामऊ दोहरीकरण (47 किलोमीटर)	414
29	वाराणसी-माधोसिंह-प्रयागराज दोहरीकरण (120 किलोमीटर)	2018
30	करैला रोड- शक्तिनगर दोहरीकरण (32 किलोमीटर)	763
31	देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रुड़की (27 किलोमीटर)	1289
32	आगरा-इटावा नई लाइन (110 किलोमीटर)	427

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	बाराबंकी-बुढ़वल तीसरी लाइन (27 किलोमीटर)	426
2	बुढ़वल- गोंडा कचहरी चौथी लाइन (56 किलोमीटर)	796
3	बुढ़वल-गोंडा तीसरी लाइन (62 किलोमीटर)	1118
4	बहराइच-खलीलाबाद नई लाइन (240 किलोमीटर)	4940

5	कटरा और अयोध्या धाम दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	466
6	पंडित दीन दयाल उपाध्याय- प्रयागराज तीसरी लाइन (150 किलोमीटर)	2649
7	बिल्ली-चुनार दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1424
8	छपरा-बलिया दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	1046
9	ऊंचाहार-अमेठी नई लाइन (66 किलोमीटर)	1229
10	एटा-कासगंज नई लाइन (29 किलोमीटर)	389
11	फेफना-इंदारा, मऊ-शाहगंज दोहरीकरण (150 किलोमीटर)	1778
12	गोरखपुर- वाल्मीकिनगर दोहरीकरण (96 किलोमीटर)	1121
13	वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय तीसरी और चौथी लाइन (15 किलोमीटर)	2464
14	झाँसी-खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन दोहरीकरण (431 किलोमीटर)	4330
15	सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन (81 किलोमीटर)	1320

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली तीन सबसे बड़ी परियोजनाओं का विवरण है:

1. श्रावस्ती, बलरामपुर, उत्तरौला, डुमरियागंज के रास्ते बहराइच-खलीलाबाद नई लाइन परियोजना (240 कि.मी.) को 4940 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। जनवरी, 2024 में इस परियोजना को राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए 'विशेष रेल परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया गया है। कार्य का निष्पादन 3 चरणों में योजना बनाकर किया गया है, अर्थात् खलीलाबाद से बंसी (54 कि.मी.), बंसी-श्रावस्ती (113 कि.मी.) और श्रावस्ती से बहराइच (73 कि.मी.)। खलीलाबाद से बंसी खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और तदनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है। मार्च 2025 तक इस परियोजना पर 1067 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और 2025-26 के लिए इस परियोजना के लिए 421 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है।
2. झाँसी-खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन (431 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजना पर 4330 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू किया गया है। परियोजना को भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के माध्यम से नवम्बर 2022 में 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया

गया है। कुल 97 हेक्टेयर में से लगभग 67 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। मार्च 2025 तक 1830 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परियोजना के लिए 1416 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। काम शुरू कर दिया गया है। 115 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है।

3. पं. दीन दयाल उपाध्याय - प्रयागराज तीसरी लाइन (150 कि.मी.) परियोजना पर 2649 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए इस परियोजना को मई 2022 में 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुल 130 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 108 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मार्च 2025 तक 1215 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परियोजना के लिए 715 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 41 कि.मी. लंबाई चालू कर दी गई है।

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 में और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 6,414 किलोमीटर कुल लंबाई को कवर करने वाले 119 सर्वेक्षण कार्य (33 नई लाइन, 84 दोहरीकरण और 02 आमामान परिवर्तन) स्वीकृत किए गए हैं।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण

- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

2023-24 से 2024-25 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में 252 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्य पूरे किए गए हैं।

01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 4689 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्यों को 1,11,583 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है, जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों के पूरा करने की प्रक्रिया पहुँच संरेखण को अंतिम रूप देने, सामान्य आरेख व्यवस्था का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, बाधक जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष/कार्य स्थलों के लिए एक वर्ष में कार्य संबंधी महीनों की वास्तविक संख्या आदि कारकों पर निर्भर करती है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल है:-

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान,

- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान,
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान,
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आजमगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदायूं, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जं., बरेली, बरेली सिटी, बड़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर,

	<p>दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गाजियाबाद, गाज़ीपुर सिटी, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासों रोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उत्तर रेलवे, लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे), मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, मगहर, महाराजा बिजली पासी, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्हौर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मारियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जंक्शन, फूलपुर, पीलीभीत जंक्शन, पोखरायां, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हाल्ट, रामपुर जंक्शन, रेनुकूट, सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जंक्शन, शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर जंक्शन, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जंक्शन, उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जंक्शन, उत्तरेतिया जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, व्यासनगर, जाफराबाद</p>
--	---

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 22 स्टेशनों (अयोध्या धाम, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, मैलानी, पनकी धाम, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी) पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं और उपर्युक्त में से कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- तुलसीपुर स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर और संकेतकों में सुधार संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- गोंडा स्टेशन: नए स्टेशन भवन के निर्माण, मौजूदा संरचनाओं को तोड़ने और जनोपयोगिताओं के स्थानांतरण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- मोदीनगर स्टेशन: स्टेशन भवन की ऊंचाई बढ़ाने, प्रतीक्षालय और शौचालय में सुधार, 12 मीटर चौड़ा पैदल पार पुल, नए प्लेटफार्म शेल्टर के कार्य पूरे कर लिए गए हैं और भवन के छोटे-मोटे अंतिम सुधार कार्य, प्लेटफार्म की सतह संबंधी कार्य, संकेतक, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
- लखनऊ (चारबाग) स्टेशन: स्टेशन भवन के दूसरे प्रवेश द्वार, टीटीई रनिंग हॉस्टल, भंडार डिपो के संरचनात्मक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और ईंट-पत्थर के कार्य सहित अन्य फिनिशिंग कार्य, कॉनकोर्स, पैदल पार पुल, दूसरे प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र, मुख्य प्रवेश द्वार पर बाहरी विकास कार्य और प्लेटफार्म क्र. 10/11 के कार्य शुरू किए गए हैं।

- प्रयागराज जंक्शन स्टेशन: दूसरे प्रवेश द्वार की ओर, रेल डाक सेवा और आगमन, पार्सल और आगमन भवनों तथा दूसरे प्रवेश द्वार पर बेसमेंट प्लाजा, विद्युत उप-केंद्र सब-स्टेशन के संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और इन संरचनाओं के फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं। पैदल पार पुल सं.2 का विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है। रूफ प्लाजा और स्थानांतरित संरचनाओं के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- गाजियाबाद स्टेशन: मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य, पैदल पार पुल की नींव का कार्य, रूफ प्लाज़ा, मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर विद्युत उप-केंद्र, मजिस्ट्रेट भवन, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के भवनों के कार्य शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के प्रावधान सहित स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों को स्वीकृति देते और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पाँच क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,358 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (अक्टूबर, 2025 तक) 2,288 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, विद्युत/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस चरण पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ (ओएसओपी) योजना रेल मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करना और रेल यात्रियों को भारत की धरोहर विरासत का अनुभव कराना और स्थानीय/स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारतीय रेल स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी आउटलेट (स्थायी स्टॉल/पोर्टेबल ट्रॉलियां) उपलब्ध कराती है।

05.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना के तहत 201 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद यूनिटों को कमीशन किया जा चुका है।
